ईंधन मूल्य का ऑप्टिक्स

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

08 नवम्बर, 2021

वैश्विक तेल की कीमतों में जारी उछाल के प्रभाव को कम करने के लिए लेवी में और कटौती की जानी चाहिए।

केन्द्र ने आखिरकार पिछले हफ्ते पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः ₹ 5 और ₹10 प्रति लीटर की कटौती करके मौद्रिक नीति निर्माताओं की सलाह पर भरोसा करने और कार्रवाई करने का फैसला किया। दीपावली की पूर्व संध्या पर घोषित शुल्क में कमी ने दोनों ईंधनों की खुदरा कीमतों को क्रमशः कम से कम 5% और 11% कम करने में मदद की। और सरकार के आग्रह पर, 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी ईंधन उत्पादों पर लगाए गए वैट को कम कर दिया, जिससे उपभोक्ताओं को रिकॉर्ड कीमतों से राहत मिली। जबकि केंद्र ने जोर देकर कहा कि यह निर्णय उभरती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ-साथ मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए था। इसके समय के राजनीतिक महत्व को नजरअंदाज करना कठिन था, एक दिन पहले ही सत्तारूढ़ भाजपा को कुछ विधायी और संसदीय उपचुनावों में हार का सामना करना पड़ा।

केन्द्र सरकार का इस निर्णय से राजनीतिक पूंजी कमाने का आशय दो दिन बाद ही स्पष्ट हो गया जब उसने भाजपा और एनडीए शासित राज्यों पर भी वैट कम करने को कह कर विपक्ष शासित राज्यों पर दबाब बना दिया। आने वाले समय में देश के राजनीति की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राज्य यू.पी. में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में है और यही वजह है कि सरकार के इस निर्णय को राजनीतिक हितोनुरूप उठाया गया कदम बताया जा रहा है। भाजपा वर्तमान मुद्दे पर नियंत्रण हासिल करने के लिए उत्सुक है, विशेष रूप से मुद्रास्फीति और ईंधन की कीमतों में वृद्धि पर जनता की बढ़ती चिंता को देखते हुए।

जहाँ तक अर्थव्यवस्था का संबंध है, ईंधन कीमतों में कमी का मुद्रास्फीति पर लाभकारी प्रभाव होना तय है क्योंकि डीजल माल ढुलाई के लिए मुख्य ईंधन है और परिवहन के लिए आवश्यक हर चीज की लागत को प्रभावित करता है। परिवहन लागत में नरमी से विनिर्माण क्षेत्र को कुछ राहत मिलनी चाहिए, जिसे ऐसे समय में बढ़ती इनपुट कीमतों का सामना करना पड़ा है जब मांग अभी भी कमजोर है।

उपभोक्ताओं के पास में बचा हुआ अतिरिक्त कैश भी खपत में एक छोटा उछाल प्रदान कर सकता है, हालांकि इस प्रोत्साहन का स्थायित्व इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले हफ्तों और महीनों में वैश्विक तेल की कीमतें कैसे व्यवहार करती हैं। इस साल वैश्विक तेल की कीमतों में उबाल रहा है और विश्व बैंक समूह ने पिछले महीने अनुमान लगाया था कि औसत कच्चे तेल की कीमतें 2021 में लगभग 70% की बढ़त के साथ समाप्त होंगी।

अक्टूबर से भारतीय कच्चे तेल की बास्केट में पिछले 10 महीनों की तुलना में औसतन लगभग 62% वृद्धि हुई है और ऐतिहासिक प्रवृत्ति रही है कि वर्ष के अंत में कीमतों में बढोत्तरी होती है। जैसे-जैसे उत्तरी गोलार्ध में सर्दी बढ़ती है वैसे-वैसे आमतौर पर ऊर्जा की मांग बढ़ती है।

इसीलिए एक वास्तविक जोखिम यह है कि भारतीय रिफाइनरियों के पास खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

इसके बाद फिर से केंद्र की जिम्मेदारी होगी कि वह पिछले साल बढ़ाये गए शुल्क में और कटौती करे। विपक्षी दलों द्वारा चलाए जा रहे राज्यों को तमिलनाडु और पंजाब से प्रेरणा लेनी चाहिए और आउटलेट्स पर कीमतें कम करनी चाहिए, न कि राजनीतिक या राजस्व कारणों से पीछे हटना चाहिए।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. हाल ही में केन्द्र सरकार ने तेल की कीमतों में कमी के लिए क्या कदम उठाया है?

(a) उत्पाद शुल्क में कमी की है।

(b) सेस को खत्म किया है।

(c) आयात शुल्क में कमी की है।

(d) उपर्युक्त सभी

Expected Question (Prelims Exams)

Q. What step has the central government taken recently to reduce oil prices?

(a) Excise duty has been reduced.

(b) Cess has been abolished.

(c) Reduction in import duty.

(d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा तेल कीमतों में की गई कमी किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी सिद्ध होगी? सोदाहरण चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Q. How the recent reduction in oil prices by the central government will prove beneficial for the Indian economy? Discuss for example. (250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।